भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1113
05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एआई-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग

†1113. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्यों में रोग के प्रसार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैटर्न और जन स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के बारे में रियल टाइम में पता लगाने के लिए एआई-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के अधिकाधिक उपयोग का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बेहतर पूर्वानुमान, निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के लिए केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के स्वास्थ्य डेटा प्लेटफ़ॉर्म को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ समेकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;
(ग) क्या सरकार की विशिष्ट विश्लेषण के लिए, विशेषकर सुदूर, जनजातीय और उच्च-संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य खुफिया इकाइयाँ स्थापित करने की योजना है; और
(घ) यदि हाँ, तो जन स्वास्थ्य संस्थानों एवं अनुसंधान निकायों के सहयोग से क्षमता निर्माण, डेटा गवर्नेंस, एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और ऐसी प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रस्तावित रूपरेखा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को प्रकोप-प्रवण संचारी रोगों की निगरानी और अनुक्रिया हेतु अधिदेशित किया गया है। आईडीएसपी अप्रैल 2022 से मीडिया स्कैनिंग और सत्यापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरणों का उपयोग कर रहा है ताकि प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाया जा सके और संभावित प्रकोपों के समय पर प्रबंधन हेतु अलर्ट जारी किए जा सकें।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) एक कागज़ रहित, मामला-आधारित, लगभग उचित समय की रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय रोग निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। सभी 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आईएचआईपी के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं, जो ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन-स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के विकास में सहयोग हेतु शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), निक्षय पोर्टल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) और गैर-संचारी रोग (एनसीडी) सहित कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्लेटफार्मों को एबीडीएम के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को एबीडीएम सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में मदद मिलती है ताकि पूरे पारितंत्र में निर्बाध अंतर-प्रचालन हो सके। ये उपाय डिजिटल रिकॉर्ड के निर्माण को सक्षम बनाते हैं, जिससे इसे पूर्वानुमान विश्लेषण, रोग निगरानी और त्वरित अनुक्रिया सहित डेटा विश्लेषण के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

रोग निगरानी, प्रकोप जांच, रेफरल डायग्नोस्टिक सेवाओं और त्वरित अनुक्रिया के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता को समर्थन और बढ़ावा देने, प्रकोप को नियंत्रित करने और उससे निपटने के लिए क्षेत्रीय और राज्य एनसीडीसी शाखाओं की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय जनता को लाभ होगा।

*****